का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, सरकार ने अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए कदम उठाए हैं। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है तथा स्थान संबंधी कतिपय प्रतिबंधों की शर्तों पर इसे उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गयी है। अतः नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है तथा लोहा और इस्पात उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इनमें ऐसे उद्योगों के लिए 51 प्रतिशत विदेशी साम्या निवेश हेतु स्वतः अनुमोदन तथा कुछ शर्तों सहित विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के लिए प्रावधान हैं।

Losses of Visvesvaraya Iron and Steel Limited

1699. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether the Visvesvaraya Iron and Steel Limited (Karnataka), a subsidiary of the Steel Authority of India Limited, is soon going the Indian Iron and Steel Company, Burnpur (IISCO) way;

(b) if so, the accumulated losses sustained by it as per latest information available with his Ministry;

(c) whether it is still incurring heavy losses;

(d) if so, the reasons for VISL's affliction and what are the major factor driving South India's only integrated steel plant to the sick bay; and

(e) what steps Government propose to take to save this one-time efficiently managed and profit-earning plant before it heads or a referral to the Board of Industrial and Financial Reconstruction (B I F R) ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) to (e) During the second half of the 1980's, Goverment of Karnataka requested Government of India to take over VISL as it was a sick unit requiring technological, financial and managerial support for its revitalisation. Accordingly, SAIL became a majority shareholder of the company in August 1989 after the terms and conditions of the take over were negotiated between the two Governments.

Since the take over of VISL by SAIL several technological and managerial decisions have been implemented, such as product mix improvement, widening of market base, training of manpower, which has resulted in improvement of performance in the Plant. In addition various projects have been implemented under the technological and managerial guidance of SAIL. SAIL has provided funds for VISL for improving its capital expenditure and working capital needs. Purchase and price preference was given to VISL by SAIL in purchase of ferro silicon.

As a result of the above measures, VISL showed continuous improvement in its profitability for a period of 3 continuous years after the take over as there was no cash loss. However, there have been three massive power tariff hikes by Karnataka Electricity Board since the take over, which has cast a heavy financial burden on VISL. The latest accumulated loss as per audited accounts on 31-3-93 is Rs. 66.30 crores. The main reasons for VISL's heavy losses inspite of improvement in its production and techno-economics, are the high power tariff, recession in demand of alloy steels and outmoded and obsolete technology. To make VISL financially viable, certain proposals have been drawn up, which have been taken up with Karnataka Government which holds a 40% stake in the Company. These are under discussion with the Government of Karnataka.

Iron-ore production in Chiria Iron ore Mines

1700. SHRI PARMESHWAR KUMAR GARWALLA : Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) what are the details regarding production of iron-ore, qurlity wise, in chiria Iron Ore Mines during the 3 years:

(b) the total iron ore reserves actually exploited or in existence; and

(c) the value of machinery employed indicating its Original values as well as written down value ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) Details of iron ore production in Chiria Iron Ore Mines during the last three years are as under :

Year	Production in MT	Quality Fe%
1991	2,49,730.87	62.00%
1992	2,58,840.80	62.02%
1993	2,57,236.82	62.04%

(b) The total iron ore reserves as on date are estimated to be 2,000 million tonnes.

(c) The value of machinery employed indicating its Original values as well as written down value, as informed by Steel Authority of India Limited, is given below :

(i) Original value audited as on 31-3-93 Rs. 101.30 lakh

(ii) Written down value audited as on 31-3-93 Rs. 45.42 lakh

निजी क्षेत्र में नए इस्पात उद्योगों की स्थापना

1701. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नए इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत जुलाई, 1991 से जनवरी, 1994 तक सरकार को कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन प्रस्तावों के अनुसार देश में इस्पात उद्योग को कितनी अतिरिक्त क्षमता पैदा किए जाने और कितनी अतिरिक्त पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, कितने नामंजूर किए गए हैं, कितने विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे स्थान संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गयी है । अतः नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और अब उद्योगियों को केवल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है ।

जुलाई, 1991 से इस्पात और इस्पात-आधारित उद्योगों के लिए 1000 से अधिक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं । इन औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों से सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता तथा उन पर अतिरिक्त निवेश इस बात पर निर्भर करेगा कि इनमें से कितनी परियोजनाएं वास्तविक रूप से कार्यान्वित की जाती हैं ।

ऐंटी डम्पिंग कानून बनाए जाने के लिए भारती इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का अनुरोध ।

1702. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :